भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं.4613

जिसका उत्तर 31.03.2022 को दिया जाना है

बैटरी स्वैपिंग नीति

4613. श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:
श्री बी.वाई.राघवेन्द्र:
श्री प्रताप सिम्हा:
डॉ. उमेश जी.जाधव:
श्री एस.मुनिस्वामी:
श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) उक्त नीति के प्रारूपण और कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बैटरी पैकों की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ): केंद्रीय बजट 2022-2023 के दौरान, सरकार ने एक बैटरी स्वैपिंग नीति और पारस्परिक प्रचालन मानक शुरू करने की योजना की घोषणा की है: -

“शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए जगह की कमी को ध्यान में रखते हुए, एक बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी और पारस्परिक प्रचालन मानक तैयार किए जाएंगे। 'सेवा के रूप में बैटरी या ऊर्जा' के लिए टिकाऊ और नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे ईवी इकोसिस्टम की दक्षता में सुधार होगा।"

नीति आयोग सभी संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर बैटरी स्वैपिंग नीति और बैटरी स्वैपिंग मानकों को तैयार करने का नेतृत्व कर रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 12 अगस्त, 2020 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि बिना बैटरी वाले वाहनों को टेस्ट एजेंसी द्वारा जारी टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र के आधार पर बेचा और पंजीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया गया कि केंद्रीय मोटर यान नियमावली (सीएमवीआर) 1989 के अनुसार, पंजीकरण के उद्देश्य से बैटरी के मेक/टाइप या किसी अन्य विवरण को निर्दिष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

*****